4

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

## भारतनेट के दूसरे चरण की शुरूआत, राज्यों के साथ समझौता और नेटवर्क के उपयोग पर राष्ट्रीय सम्मेलन

Posted On: 12 NOV 2017 7:10PM by PIB Delhi

- भारतनेट के पहले चरण में 1 लाख ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टीविटी उपलब्ध कराई गई, दूरसंचार विभाग ने इन स्थानों पर ब्राडबैंड आधारित नागरिक सेवाएं प्रदान करने के बारे में चर्चा शुरू की
- 🔹 राज्यों के साथ समझौता पत्रों पर हस्ताक्षर और नेटवर्क के उपयोग पर 13 नवंबर 2017 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन, राज्य और सेवा प्रदाता भी शामिल होंगे
- एयरटेल, रिलायंस जिओ, वोडापोन और आइंडिया जैसी दूरसंचार कंपनियों ने भारतनेट ढांचे में सहयोग के प्रति रुचि दिखाई
- भारतनेट के दूसरे चरण को लागू करने करने के लिए राज्यों के साथ समझौता पत्रों पर हस्ताक्षर होंगे

दूरसंचार विभाग सोमवार (13 नवंबर 2017) को भारतनेट ढांचे से लाभ उठाने और इसके विविध आयामों के बारे में चर्चा के लिए राज्य सरकारों और सेवा प्रदाताओं के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इस सम्मेलन में राज्यों के सूचना प्रोद्योगिकी मंत्री और सूचना प्रोद्योगिकी सचिव भाग लेंगे।

भारतनेट के पहले चरण में देशभर की एक लाख ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पर ब्राडबैंड ढांचा उपलब्ध कराया गया है। राज्य सरकारें भारतनेट ढांचे से लाभ उठाने के बारे में अपनी योजनाओं को साझा करेंगी। दूरसंचार विभाग भारतनेट से मिलने वाली सेवाओं के बारे में कई जानकारियां देगा तािक नेटवर्क से अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सके। दूरसंचार विभाग के सहयोगी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने ग्रामीण इलाकों में भारतनेट ढांचे से जुड़ी सेवाओं के बारे में जानकारी देने के लिए केंद्र शुरू करने की पहल की है। सम्मेलन में ये प्रदाता अपने अनुभवों को साझा करेंगे।

दूरसंचार विभाग ने पहले चरण के तहत काम को पूरा करने के लिए पिछले 6 माह में तेजी दिखाई है। भारतनेट के पहले चरण में देश के कई राज्यों की 1 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टीविटी उपलब्ध कराई गई है। दिसंबर 2017 तक सभी एक लाख ग्राम पंचायतों में भारतनेट ढांचा काम करना शुरू कर देगा। वर्तमान में 90 हजार से अधिक पंचायतों में कार्य हो चुका है और 80 हजार ग्राम पंचायतों में भी सेवाएं जल्द शुरू होंगी।

सम्मेलन में दूरसंचार विभाग भारतनेट के दूसरे चरण को लागू करने के लिए राज्यों के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करेगा।

वीके/बीपी/सीएल -5406

(Release ID: 1509118) Visitor Counter: 31









in

